शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 43 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 14 – 21 अक्तूबर 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या कर्मचारियों की संख्या कम करके प्रदेश आत्मनिर्भर हो जायेगा?

- क्या बिजली बोर्ड को प्राइवेट सैक्टर को देने पर विचार हो रहा है?
- क्या राजस्व आय और व्यय बराबर करने के लिये आम आदमी पर करों का बोझ डालना आवश्यक है?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने जब प्रदेश की बागडोर दिसम्बर 2022 में संभाली थी तब प्रदेश की जनता को यह चेतावनी दी थी कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं । इसी चेतावनी के साये में पिछली सरकार द्वारा अंतिम छः माह में लिये फैसले पलटते हुये सैकड़ो नए खोले संस्थान बंद कर दिये। पैट्रोल, डीजल पर वैट बढ़ाया । शहरी क्षेत्रों में पानी के रेट बढ़ाये जो अब गांव तक जा पहुचे हैं। जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी वह सुविधा बंद कर दी गयी। कुल मिलाकर आम आदमी की जेब से जिस भी नाम से जो भी निकाला जा सकता था वह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निकाल दिया गया। यहां तक के टॉयलेट टैक्स और बसों में यात्रा करते समय साथ ले जा रहे सामान पर भी यदि वह 5 किलो से अधिक है तो उस पर भी किराया लगा दिया गया। जब इस पर शोर उठा तो इसमें संशोधन कर दिये गये। अब बिजली बोर्ड से 51 अभियंताओं के पद समाप्त करने के साथ ही 81 ड्राइवरो को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है । बिजली बोर्ड को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके उसमें कर्मचारियों की संख्या आधी करने की चर्चा है। सुक्खू सरकार ने 2026 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का और 2030 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य घोषित कर रखा है। कोई भी प्रदेश तब आत्मनिर्भर बनता है जब उसका राजस्व व्यय और राजस्व आय बराबर हो जाए। इस समय यदि राजस्व आय और व्यय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020-21 में आय व्यय में 1.19%, 2021-22 में 3.95 %, 2022-23 में 4.98%, 2023-24 में 6.14% और 2024-25 में 7.44 % घाटा रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा इसी अवधि में 4.12%, 4.52%, 4.57%, 4.82% और 2024-25 में 4.98% रहने की संभावना है। घाटे के इन आंकड़ों को पार कर प्रदेश को बराबरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। राजस्व व्यय में सबसे ज्यादा खर्च वेतन पर 25.13 प्रतिशत और पैंशन पर 17.04 प्रतिशत होता है। इसके बाद ब्याज पर 10.70 प्रतिशत और ऋण अदायगी पर 9.42 प्रतिशत खर्च हो रहा है। इन खर्चो को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना सबसे पहले एजेंडा है। इसी एजेंडे के तहत बिजली बोर्ड अभियंताओं के पद समाप्त किए गए हैं। स्वभाविक है कि जब यह पद समाप्त हो जाएंगे तो इसका असर नीचे कर्मचारी तक पड़ेगा। इसी योजना के तहत बिजली बोर्ड और कुछ अन्य नियमों बोर्डो को प्राइवेट सैक्टर को देने की योजना है। सरकार में नियमित भर्ती बहुत अरसे से लगभग बंद है। अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के आदेश पारित किए गए हैं। जब दो वर्ष पहले इस बोर्ड को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत भंग किया गया था तब इसमें कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए थे। कई गिरफ्तारियां हुई थी। परंतु अभी तक अदालत से शायद एक भी मामले का फैसला नहीं आया है। किसी को भी सजा घोषित नहीं हुई है। ऐसे में क्या इन परीक्षाओं के परिणाम पहले नहीं घोषित किये जा सकते थे। क्या इन परिणामों में हुई देरी भी खर्च कम करने का ही एक प्रयोग था। आज केंद्र में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष तक राहुल गांधी के पदयात्रा और सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट सैक्टर को देने के खिलाफ उभरे रोष के परिणाम स्वरुप पहुंची है। राहुल लगातार प्राइवेट सैक्टर की लूट के खिलाफ मुखर रहे हैं। प्रैस की स्वतंत्रता के पक्षधर है। लेकिन उनकी ही पार्टी की सरकार हिमाचल में बिजली बोर्ड जैसी उपक्रमों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की योजना पर काम कर रही है। बिजली की खरीद बेच का काम बोर्ड से ले लिया गया है। एक समय हिमाचल को इसी बोर्ड के सहारे प्रदेश को बिजली राज्य घोषित करके उद्योगों को आमंत्रि किया जाता था। आज इसी बिजली बोर्ड की बढ़ी हुई दरों के कारण उद्योग पलायन करने के कगार पर आ पहुंचे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि क्या कर्मचारीयों की संख्या कम करके और आम आदमी पर करों का बोझ लादकर 2026 में प्रदेश आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

प्ररूप–1
(नियम 4 और 5 देखें)
मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण

क. राजकोषीय सूचल–चल (रोलिंग) लक्ष्यः (₹ करोड़ों में)

	राजकोषीय सूचक	चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन 2020-21	आगामी वर्ष लक्ष्य बजट प्राक्कलन वर्ष 2021-22	अगले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य		
				वर्ष+1 2022-23	वर्ष+2 2023-24	वर्ष+3 2024-25
1.	राजस्व प्राप्तियां	35588.36	37027.94	39199.30*	41438.73*	43732.09*
2.	राजस्व व्यय	36010.95	38490.88	41150.40	43984.32	46986.05
3.	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा/लाभ	–1.19	–3.95	–4.98	–6.14	–7.44
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा	–4.12	–4.52	–4.67	–4.82	–4.98
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व	5.06	5.39	5.59	5.79	6.00
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय ऋण	39.33	40.26	40.60	39.91	39.28
7.	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां	6.07	7.66	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम की सीमा के भीतर रहने की संभावना है।		
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	156522	172174	189392	208331	229164

* जीएसटीo क्षतिपूर्ति को जून, 2022 के बाद भी राजस्व प्राप्तियों में कल्पित/शामिल किया गया है।

राज्यपाल ने निर्मल ठाकुर को प्रथम सप्त सिंधु लाइफटाइम अवार्ड प्रदान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में निर्मल ठाकुर को शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सप्त सिंधु फाउंडेशन दिल्ली द्वारा आयोजित प्रथम महाराजा दाहिर सेन सप्त

सिंधु लाइफटाइम अवार्ड प्रदान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने फाउंडेशन को महाराजा दाहिर सेन के नाम पर सप्त सिंधु अवार्ड स्थापित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि वेदों में सप्त सिंधु का उल्लेख है।

राज्यपाल ने कहा कि यह सात नदियों का बहुत व्यापक क्षेत्र था जिसमें चार नदियां सतलुज, ब्यास, चिनाव और रावी हिमाचल प्रदेश से बहकर जाती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सप्त सिंधु क्षेत्र की देवभूमि भी कहा जाता है। राज्यपाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि पहला सप्त सिंधु अवार्ड कार्यक्रम भी हिमाचल में ही आयोजित हुआ।

उन्होंने कहा कि सिंधु नरेश महाराजा दाहिर सेन ने आक्रमणकारियों से कभी समझौता न कर उनके खिलाफ संघर्ष किया और देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे महान और शूरवीर शख्सियत को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि महाराजा दाहिर सेन के नाम पर दिया जाने वाला यह सप्त सिंधु लाइफटाइम पुरस्कार इतिहासकारों को समीक्षा का अवसर भी प्रदान करेगा।

राज्यपाल ने निर्मल ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि वह जीवन पर्यन्त इस क्षेत्र से जुड़ी रहीं तथा हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया। उनका सम्मान पूरे प्रदेश के लोगों का सम्मान है। राज्यपाल ने कहा कि निर्मल ठाकुर द्वारा शिक्षित छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान उसके विद्यार्थी होते हैं। जब शिक्षक द्वारा शिक्षित छात्र जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो शिक्षक को खुशी की चरम अनुभूति होती है। राज्यपाल ने कहा कि निर्मल ठाकुर अपनी काव्य रचनाओं के जरिए साहित्य के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है और बहुत ख्याति प्राप्त की है।

उन्होंने कहा कि रियल्म ऑफ थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ उनके दो ऐसे काव्य संग्रह है जिसने उन्हें हिमाचल प्रदेश की साहित्यिक दुनिया में पहचान दिलाई। राज्यपाल ने कहा कि उनकी कविताएं भावनात्मक हैं और जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 90 वर्ष की आयु में भी वह प्रदेश में हो रही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं।

निर्मल ठाकुर ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा यह पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उनका मनोबल बढ़ा है तथा इससे उन्हें एक लेखिका के रूप में अपनी कलम की ताकत को और मजबूत करने का प्रोत्साहन मिला है।

उन्होंने कहा कि जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हर कदम पर अपने परिवार के सहयोग और संबल की आवश्यकता होती है और इसके लिए वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं क्योंकि यह सब उन्हें परिवार से भरपूर मिला।

राज्यपाल ने अटल टनल को दौरा कर एस्केप टनल में सुविधाओं की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी धर्मपत्नी जानकी

शुक्ल के साथ अटल टनल का दौरा किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के वरिष्ठ अधिकारियों से एस्केप (निकास) टनल के बारे में जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल ने कहा कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित 9 किलोमीटर लम्बी यह विश्व की सबसे ऊंची राजमार्ग सिंगल-ट्यूब टनल है, जो जिला लाहौल-स्पीति तथा कुल्लू के दोनों तरफ के क्षेत्रों को जोड़ती है। यह टनल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा स्थानीय लोगों के लिए वर्ष भर सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे मनाली-केलांग-लेह के बीच दूरी घटने से यात्रा का समय भी कम हुआ है।

बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर संदीप सिंह ने राज्यपाल को एस्केप टनल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह टनल प्रत्येक 400 मीटर पर खुलती है। उन्होंने कहा कि यह टनल उन अधिकांश स्थानों को बाईपास करती है, जो हिमस्खलन और यातायात की दृष्टि से संवेदनशील हैं।

जिला लाहौल-स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने टनल के नॉर्थ पोर्टल पर राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने सिस्सू झील का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आने वाले सैलानियों की यात्रा लाहौल की खूबसूरत घाटियों का आनन्द लिये बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बीआरओ के माध्यम से इस क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधाएं प्रदान की गई हैं और प्रदेश सरकार पर्यटकों और क्षेत्रवासियों को अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही हैं।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हालांकि पूरा हिमाचल बेहद खूबसूरत है, लेकिन लाहौल की सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमें इसकी पवित्रता, वातावरण और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

बच्चों को पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां सीखने के लिए करें प्रेरितःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिला के जुन्गा में चार दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हास्पिटैलिटी एक्सपो-2024 का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को

पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए तभी ऐसे फ्लाइंग फेस्टिवल सफल होंगे।

राज्यपाल ने कहा कि लोग शायद ही देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी के नाम जानते हो लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का नाम सबको पता है और इसकी अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान है। उन्होंने आयोजनकर्ता अरुण रावत और उनकी टीम को फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजन के लिए बधाई दी और क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन से निश्चित ही पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिलेगा और क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि सेब की फसल से ही प्रदेश की आर्थिकी 5500 करोड़ रूपए की है और फ्लाइंग फेस्टिवल जैसी गतिविधियों से आर्थिकी और सुदृढ़ होगी। अकेले मनाली में 3000 से ज्यादा होटल हैं जोकि अन्य राज्यों से आने वाले सैलानियों का प्रदेश के प्रति लगाव को दर्शाता है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का असल लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई से जुड़ी संस्थाएं तभी सफल होंगी जब उनके उत्पादों को बाजार उपलप्ध होगा। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों के उत्पादों को बाहर देशों में भेजने के प्रयास करने के निर्देश भी दिए।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।

आयोजनकर्ता अरुण रावत ने शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2024 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस पुलिस लाइन भरारी में मनाया गया हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों द्वारा यहां परेड संपन्न की गई जिसका नेतृत्व अदिति सिंह भा0पु0से0 द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूरे वर्ष में देश भर में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए जवानों के नाम का स्मरण अभिषेक त्रिवेदी भा0पु0से0 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों जिसमें पुलिस उप महानिदेशक रंजना चौहान, गुरुदेव शर्मा, राहुल नाथ आदि सहित सेवानिवृत अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे तथा उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्कर अर्पित किये। समस्त स्तर के विभिन्न पुलिस कर्मचारियों ने भी शहीदों को नमन करके पुष्पांजलि अर्पित की इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला व वाहिनी मुख्यालय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

32वीं बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में 32वीं हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस-2024 का आयोजन 18 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2024 तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18-19 और 21-22 अक्तूबर को यह सम्मेलन प्रदेश के 73 उप-मंडलों में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 6 और 8 नवम्बर को प्रदेश के सभी जिलों में तथा 13 और 14 नवम्बर को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रचार और प्रसार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पाठयक्रमों में कृत्रिम मेधा व तकनीक आधारित विषयों का समावेश किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग ले रहे सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके उत्साह और समर्पण से राज्य में विज्ञान के भविष्य को नया आकार मिलेगा।

32वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में लगभग 22 हजार विद्यार्थी और आठ हजार शिक्षक भाग ले रहे हैं।

चैलचौक-पंडोह व मंडी-बजौरा मार्गों के लिए 21.05 करोड़ रुपये स्वीकृतःविक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चैलचौक-गोहर-पंडोह और मंडी-कमान्द-कटौला-बजौरा मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 21.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि चौलचौक-गोहर-पंडोह के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 9.16 करोड़ रुपये तथा मंडी-कमान्द-कटौला-बजौरा के लिए 11.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही के दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें इन राजमार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव की आवश्यकताओं से अवगत करवाया था तथा इनके लिए पर्याप्त धनराशि की मांग उठाई थी।

विक्रमादित्य सिंह ने कम समयावधि के भीतर प्रदेशहित के दृष्टिगत इन राजमार्गो के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चैलचौक-पंडोह मार्ग के बरसात के दौरान लगातार अवरुद्ध होने के कारण मंडी-बजौरा मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में केंद्र द्वारा धनराशि स्वीकृति करना स्थानीय लोगों और कुल्लू की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत, बजंतरियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20–20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू नेअंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा–2024 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए देवी–देवताओं के नजराने में पांच प्रतिशत, बजंतरियों

के मानदेय और दूरी भत्ते में 20–20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कुल्लू जिला के पिरडी में ब्यास नदी के लेफ्ट और राइट बैंक को जोड़ने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से पुल के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भूभू–जोत टनल का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया गया है और राज्य सरकार इस टनल के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने मनाली के हरिपुर में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू में 100 बिस्तर क्षमता वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल को राज्य सरकार सुदृढ़ करेगी ताकि जिला के लोगों को यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू के सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूहल में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पर्याप्त डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। कुल्लू जिला अस्पताल में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कार्यों के लिए लोक निर्माण मंडल कुल्लू को आठ करोड़ रुपये और मनाली मंडल को पांच करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अंतराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा–2024 में देवी–देवताओं को देवताओं की पुरानी वेशभूषा, वाद्ययंत्रों की धुनों, रथों की सजावट व शिविरों की सुंदरता व सफाई रखने के लिए देवी–देवताओं के कारदारों को पुरस्कृत किया। देवता श्री बिजली महादेव के कारदार अमर नाथ को प्रथम पुरस्कार, देवी श्री माता ज्वालामुखी फोजल के कारदार अमर चंद को द्वितीय पुरस्कार और देवी श्री माता पंचालिका राजेश्वरी के कारदार धनी राम को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सूत्रधार कला संगम को प्रथम, सूर्य सांस्कृतिक दल को द्वितीय और भुठी विवरज सांस्कृतिक दल को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने भगवान रघुनाथ के शिविर में पूजा–अर्चना कर प्रदेश में सुख–समृद्धि की कामना की। उन्होंने कुल्लू कार्निवाल को हरी झंडी दिखाई। इस कार्निवाल में 600 से ज्यादा महिलाओं और कलाकारों ने भाग लिया जिसमें छः अंतरराष्ट्रीय दल, विभिन्न स्कूल, विभागों की झांकियां और 30 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं शामिल हुई।

मुख्यमंत्री ने जिला कुल्लू के पिरडी में 273 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बिजली महादेव रोपवे के बेस स्टेशन की साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रोपवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार को एफसीए क्लीयरेंस मिल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने पिरडी में प्रस्तावित राजीव गांधी–डे बोर्डिंग स्कूल और ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने हाथीथान में पर्यटन विभाग के माध्यम से तैयार किए जा रहे वे–साइड एमिनिटिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

पंजाब सरकार को शानन का संचालन हिमाचल को सौंप देना चाहिए:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जोगिन्द्रनगर स्थित 110 मेगावाट क्षमता के ऐतिहासिक शानन पावर हाऊस का दौरा किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टरबाइन, अल्टरनेटर, एक्साइटर, कंट्रोल रूम सहित पावर हाऊस के विभिन्न सेक्शन का दौरा किया और अधिकारियों से यहां विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बरोट से पावर हाऊस तक पानी लाने के लिए उपयोग में लाई जा रही प्राचीन ट्रॉली का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके आज के दौरे का उद्देश्य रहा है। अभी इसका संचालन पंजाब सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत चल रही है और इस बारे में पत्रचार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की लीज़ अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए पंजाब को इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपना चाहिए। इस पर हिमाचल का अधिकार बनता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को अब इसे छोटे भाई हिमाचल को सौंप देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत नहीं आती है। परियोजना को लेकर पंजाब सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी को मान्य होगा।

जनवरी, 2025 तक ऊहल परियोजना चरण तीन से शुरू हो जाएगा विद्युत उत्पादनः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में ऊहल परियोजना के तृतीय चरण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को

पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने मौके पर ही इस परियोजना की सॉवरन गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी इस वर्ष मार्च, 2024 में 100 करोड़ रुपए परियोजना को प्रदान किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से इस परियोजना का कार्य चल रहा है और इस कारण इसकी लागत भी बढ़ी है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अब इस परियोजना के कार्यो को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की तकनीकी और अन्य जांच करने के उपरांत दिसम्बर अंत या जनवरी, 2025 तक इसमें विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल के तहत टाटा पावर लिमिटेड को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त आय प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। उन्होंने परियोजना प्रबन्धकों को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन से ही हिमाचल प्रदेश समृद्ध बन सकता है और प्रदेश सरकार इसके दोहन के लिए ठोस कदम उठा रही है। हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पन विद्युत, सौर ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में विद्युत बोर्ड को लगभग 2200 करोड़ रुपए प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का प्रयास बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने का है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न कार्यो के लिए संबंधित अधिकारियों को शक्तियों के हस्तांतरण पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

इससे पूर्व ऊहल परियोजना के चरण–तीन के प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से परियोजना कार्य की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

पानी से जुड़े कानूनों को जोड़कर बनेगा अंब्रेला एक्टःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पानी से जुड़े सभी कानूनों को

जोड़कर एक अंब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की संपदा को लुटने नहीं दिया जाएगा और अदालतों में विचाराधीन मामलों की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पास सीमित संसाधन हैं, जिनका सही इस्तेमाल प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटना चुनौती है और मौसम में बदलाव के कारण बादल फटने जैसी घटनाओं में बढ़ौतरी हुई, जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के हितों की अनदेखी की, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश से इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के कारण ही राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए की एक और किश्त जारी करने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार अपने कार्यकाल में सात प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के नए भवन का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के ढली उप–नगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8.28 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। यह सुविधा हिमाचल प्रदेश में श्रवण एवं दृष्टिबाधित बच्चों को सुविधा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस पांच मंजिला भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस भवन में कम्प्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा, 10 कमरे छात्रावास के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमत्री ने कहा कि वर्तमान में इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है जिनमें 106 श्रवणबाधित और 34 दृष्टिबाधित छात्र शामिल हैं। इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, छात्रों को यहां हस्तशिल्प, बेकरी, कम्प्यूटर कौशल और बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

मै हिन्दी के जरिये प्रांतीय भाषाओं को दबाना नही चाहता, किन्तु उनके साथ हिन्दी को भी मिला देना चाहता हूं।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

ईवीएम पर उठते सवाल और कांग्रेस की विश्वसनीयता

कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए ईवीएम मशीनों पर भी दोष डाल रही है। इस बार जो आरोप इन मशीनों पर लगाया जा रहा है वह शायद पहले नहीं लगा है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मतगणना केन्द्रों में वोटो की गिनती में ऐसी मशीन सामने आयी हैं जिनकी बैटरी 99 प्रतिशत तक चार्ज थी। जबकि औसत मशीनों की बैटरी 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत थी। ऐसा 20 विधानसभा क्षेत्रों में होने का आरोप है। इसी के साथ चुनावी डाटा भी देर से साइट पर लोड करने का आरोप है। इसी डाटा के कारण तेरह लाख वोट बढ़ गये हैं। चुनाव आयोग से भी यह शिकायतें की गयी है और आयोग ने इन्हें खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस आश्य की याचिका दायर करके 20 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीने सील करने का आग्रह करके इन क्षेत्रों में पुन: चुनाव की मांग की गयी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार करता है या खारिज कर देता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन चुनाव आयोग इन आरोपों को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा और इन चुनावों के इससे प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। ईवीएम पर शुरू से आरोप उठते आये हैं। सबसे पहले इस पर भाजपा ने ही सन्देह जताया था। लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाये। इस पर एक पुस्तिका तक छापी गयी थी। हर विपक्ष हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाता आया है। लेकिन सत्ता में आने पर इसका पक्षधर बनता आया है। उन्नीस लाख ईवीएम मशीनों का रिकॉर्ड में गायब होने की जानकारी आरटीआई के माध्यम से सामने आ चुकी है। लेकिन इन मशीनों के गायब होने को किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक मुद्दा नहीं बनाया है। इसी से राजनीतिक दलों की मानसिकता स्पष्ट हो जाती है। यहां पर चुनाव हारने के बाद ईवीएम अपनी असफलता उस पर डालने का माध्यम मात्र होकर रह गया है। जबकि विदेशों में ईवीएम पर उठते सवालों के कारण बहुत देश चुनाव में मत पत्रों पर आ गये हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की रैलियों में कितनी भीड़ होती थी और प्रधानमंत्री के लिये कितने लोग आते थे यह चुनावी रैलियां में देश देख चुका है। इसी से सारे चुनाव पूर्व के आकलन में कांग्रेस की भारी जीत मानी जा रही थी। आज तक ईवीएम पर उठे सवालों के कारण एक भी चुनाव क्षेत्र का चुनाव रद्द नहीं हो पाया है। जबकि ईवीएम पर सवाल उठना अपने में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब आम आदमी भी ईवीएम को सन्देह की नजरों से देखने लग पड़ा है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सदन में ईवीएम हैक करके दिखा दी गयी थी। लेकिन जिसने यह करके दिखाया था उसका बाद में क्या हुआ और यह मुद्दा कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता। स्वयं अरविंद केजरीवाल ने भी सदन के बाहर इसे जन मुद्दा नहीं बनाया और केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया इसका कोई जवाब भी सामने नहीं आया है। ईवीएम पर उठते सवालों से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की नैतिकता पर कहीं चोट नहीं आती है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस से विनम्र आग्रह हैं कि यदि ईवीएम पर उठते सवालों से आप स्वयं में संतुष्ट है तो एक बार इस मुद्दे को जन मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने का साहस करो। एक चुनाव का हर राज्य और केंद्र में बहिष्कार कर देने का साहस दिखाओ पता चल जायेगा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार कांग्रेस के बहिष्कार के बाद ईवीएम से चुनाव करवाने का साहस दिखाते हैं या नहीं। यदि ईवीएम को मुद्दा बनाकर चुनाव बहिष्कार का साहस नहीं है तो फिर ईवीएम पर सवाल उठाने छोड़कर कांग्रेस में विश्वसनीय नेतृत्व राज्यों में लाने का प्रयास करें। इस समय कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में हैं वहां पर सरकारों की परफॉरमैन्स का ईमानदारी से फीडबैक ले। देखे की गिनती सरकारें जन अपेक्षाओं और अपने ही चुनावी वायदों के आईने में खरा उतर रही है। हिमाचल में जिस तरह से सरकार चल रही है उससे राज्यों के नेतृत्व के बजाये केंद्रीय नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लग पड़े हैं जो बहुत घातक प्रमाणित होंगे।

प्रदेश सरकार की नई योजनाओं से शिक्षा क्षेत्र को मिल रही नई दिशा

विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनका सामाजिक विकास भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षित विद्यार्थी, जिम्मेदार नागरिक बन सशक्त समाज का निर्माण करते हैं।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक नवाचार कदम उठाए हैं। ऐसी ही एक पहल है 'अपना विद्यालय: द हिमाचल स्कूल अडोशन प्रोग्राम' इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेशवासी राजकीय पाठशालाओं को गोद लेकर शिक्षा क्षेत्र के सुधार में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं।

इस योजना की मूल भावना स्कूलों के विद्यार्थियों और समाज के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों की सामूहिक भागीदारी को बढ़ाकर उन्हें सामाजिक कार्यो से जोड़ा जा रहा है और करियर परामर्श, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य विषयों का समग्र ज्ञान दिया जा रहा है।

कार्यक्रम की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 427 विद्यालयों को समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों द्वारा गोद लिया गया है। इसमें 109 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं, 9 राजकीय उच्च पाठशालाएं, 33 राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं और 285 राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं शामिल हैं।

सोशल मीडिया, नशे की प्रवृति इत्यादि आदतों से आज का युवा समाज से विमुख हो रहा है। युवाओं को समाज के प्रति जिम्मेदारियों का बोध करवाने के लिए यह योजना मील पत्थर साबित हो रही है। योजना के तहत गोद लिए गए विद्यालयों में जाकर बच्चों की करियर काउंसलिंग, नशे की बुराईयों, महिला सशक्तिकरण, कानूनी जानकारी और मौलिक कर्त्तव्यों की जानकारी दी जाती है।

कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल पैट्रन अभियान के तहत गणमान्य व्यक्ति स्कूल पैट्रन बन स्कूलों के स्टाफ और एसएमसी के साथ बैठकें आयोजित कर शिक्षा और शिक्षण में गुणात्मक सुधार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 'माई स्कूल माई अभियान' के तहत शिक्षा के साथ-साथ योगा, खेल इत्यादि गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है।

शैक्षणिक सहयोग टीमें विशेषतौर पर बच्चों के ज्ञानवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। सेवानिवृत्त अध्यापक, सरकारी और केन्द्रीय सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेशेवर इत्यादि लोग इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा, कानूनी जानकारी, पोषण आवश्यकता, नशा निवारण और रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

'अपना विद्यालय: द हिमाचल स्कूल अडोप्शन प्रोग्राम' के अन्तर्गत जिला बिलासपुर में 21, चम्बा में 48, हमीरपुर में 32, कांगड़ा में 35, किन्नौर में 2, कुल्लू में 18, मंडी में 66, शिमला में 117, सिरमौर में 1 और सोलन में 96 स्कूल गोद लिए गए हैं।

हिमाचल शिक्षा क्षेत्र में रूपान्तरकारी सुधारों के युग का साक्षी बन रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा तंत्र को स्थापित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जनसहभागिता सुनिश्चित कर शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक आ रहे हैं।

ज़िला चंबा में आंगनबाड़ी केंद्रों से 28931 बच्चों को 1495 मिल रहा है पूरक पोषाहार

स्वस्थ एवं सुपोषित बचपन नौनिहालों के भविष्य को एक मजबूत नीव प्रदान करता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के साथ बाल विकास सेवाओं के विस्तार को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास राकेश कुमार बताते हैं कि समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षी ज़िला चंबा में 1495 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु के 28931 बच्चों को वर्तमान में पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है । इसके साथ ज़िला में 7538 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 14 से 18 वर्ष तक की 17155 किशोरियों को विशेष पोषाहार कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़िला में एक सौ आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। इसके तहत बाल विकास परियोजना चंबा के अंतर्गत 21 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया गया है। इसी तरह बाल विकास परियोजना सलूणी के 20,बाल विकास परियोजना मेहला के 20,बाल विकास परियोजना तीसा के 14 तथा बाल विकास परियोजना भटीयात के तहत 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया गया है।

वह बताते हैं कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत आधारभूत संरचना से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्तमान में सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए आरओ वॉटर प्यूरीफायर स्थापित के साथ 90 केंद्र परिसरों में पोषण वाटिका तथा 65 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था भी सुनिश्चित बनाई गई है।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि चंबा ज़िला में 1495 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु के 28931 बच्चों को वर्तमान में पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है । इसके तहत बाल विकास परियोजना चंबा के अंतर्गत 4209, बाल विकास परियोजना सलूणी के तहत 5279, बाल विकास परियोजना मेहला के तहत 4852, बाल विकास परियोजना तीसा के अंतर्गत 6533, बाल विकास परियोजना भटीयात के तहत 5317, बाल विकास परियोजना भरमौर के तहत 1960 तथा बाल विकास परियोजना पांगी के तहत 779 बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में राजमाह-चावल, मीठा एवं नमकीन दलिया, खिचड़ी, काले चने, मीठी सेवइयां, बाजरा और औट के बिस्कुट इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ।

विश्व आयोडीन अल्पता दिवस

जागरूकता और कारवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना

विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिसे वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष 21 अक्तूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने

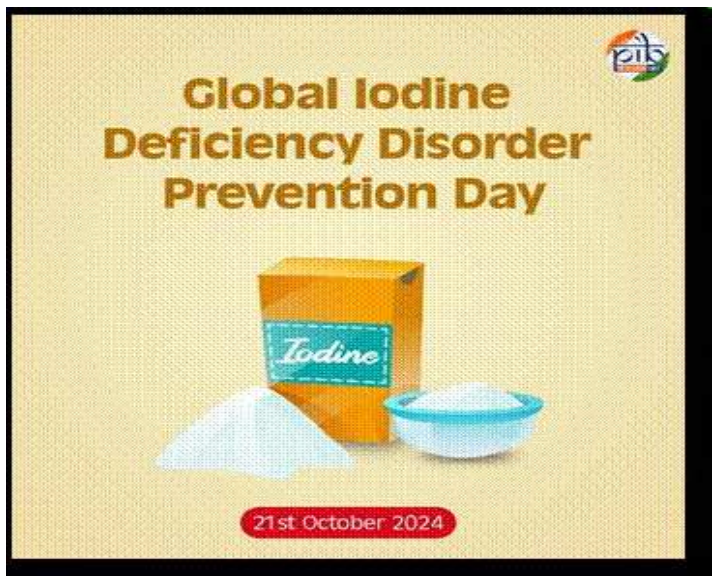

में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर बल देना है। यह दस्तावेज़ दैनिक पोषण में आयोडीन के महत्व और इसकी कमी संबंधी विकारों को रोकने में आयोडीन के महत्व को रेखांकित करता है।

आयोडीन क्या है

आयोडीन थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन टी4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन टी3 का एक आवश्यक घटक है, जो चयापचय को नियंत्रित करता है और भ्रूण तथा शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थो और आयोडीन युक्त नमक में पाया जाने वाला आयोडीन सोडियम और

पोटेशियम नमक, अकार्बनिक आयोडीन 2, आयोडेट और आयोडाइड सहित कई रूपों में मौजूद होता है। आयोडाइड, सबसे सामान्य रूप है जो पेट में तेजी से अवशोषित होता है और थायराइड द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश अतिरिक्त आयोडाइड मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है।

आयोडीन की कमी से क्या होता है?

आयोडीन की कमी से वृद्धि और विकास पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, यह निदान योग्य बौद्धिक अक्षमता का सबसे आम कारण है। अपर्याप्त आयोडीन के कारण थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है जिसके परिणामस्वरूप आयोडीन अल्पता वाले विकार होते हैं। गर्भावस्था और प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान, आयोडीन की कमी से अपरिवर्तनीय दुष्परिणाम हो सकते हैं।

- यदि किसी व्यक्ति का आयोडीन सेवन लगभग 10 – 20 एमसीजी प्रति दिन से कम होता है, तो यह स्थिति हाइपोथायरायडिज्म होता है। यह अकसर घेंघा रोग के साथ होती है। घेंघा रोग सामान्य तौर पर आयोडीन की कमी का प्रारंभिक नैदानिक संकेत है।
- आयोडीन की कमी की इस स्थिति में गर्भवती महिलाओं में भ्रूण में न्यूरोडेवलपमेंटल समस्या और विकास मंदता तथा गर्भपात और प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु होने का खतरा रहता है।
- दीर्घकालिक और अत्यधिक आयोडीन की कमी से गर्भाशय में क्रेटिनिज्म की स्थिति बन जाती है, इसमें बौद्धिक अक्षमता, बधिर मूकता, मोटर स्पास्टिसिटी, विलंबित विकास, विलंबित यौन परिपक्वता और अन्य शारीरिक तथा तंत्रिका संबंधी असामान्यताएं।
- शिशुओं और बच्चों में आयोडीन की कमी से न्यूरोडेवलपमेंटल विकार जैसे – औसत से कम बुद्धि का विकास होता है, इसे पफ द्वारा मापा जाता है।
- माताओं में हल्की से मध्यम आयोडीन की कमी से बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है।
- वयस्कों में हल्की से मध्यम आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है साथ ही हाइपोथायरायडिज्म के कारण मानसिक विकार और कार्य उत्पादकता में कमी आती है।
- दीर्घकालिक आयोडीन की कमी से थायराइड कैंसर के कूपिक रूप का जोखिम बढ़ जाता है।

आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास

आयोडीन की कमी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभावों को पहचानते हुए भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम एनजीसीपी के माध्यम से इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयास शुरू किए। इस कार्यक्रम में आयोडीन की कमी से होने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे – शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध, बौनापन और जन्म के समय मृत्यु को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गए।

1992 में, कार्यक्रम को व्यापक बनाया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम एनआईडीडीसीपी कर दिया गया। आयोडीन की कमी से होने वाले विभिन्न विकारों आईडीडी को नियंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित करना सुनिश्चित किया गया।

एनआईडीडीसीपी के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं

- देशभर में आईडीडी के प्रसार को 5% से कम करना।
- घरेलू स्तर पर पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक 15 पीपीएम आयोडीन के साथ की 100% खपत प्राप्त करना।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, यह कार्यक्रम कई प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है:

- विभिन्न जिलों में आईडीडी की गंभीरता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना।

- प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग।
- आईडीडी पर आयोडीन युक्त नमक के प्रभाव को मापने के लिए हर पांच वर्ष में पुन: सर्वेक्षण आयोजित करना।
- प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता और मूत्र में आयोडीन उत्सर्जन की निगरानी करना।
- आईडीडी को रोकने में आयोडीन की भूमिका के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना।

1984 में भारत में सभी खाद्य नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिया गया, इस पहल को 1986 से चरणबद्ध श्रृंखला के रूप में शुरू किया गया। 1992 तक, देश का लक्ष्य पूरी तरह से आयोडीन युक्त नमक में परिवर्तन करना था। भारत आज सालाना 65 लाख मीट्रिक टन आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन करता है, जो इसकी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में भी जारी यह राष्ट्रीय प्रयास आयोडीन की कमी को दूर करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम एनआईडीडीसीपी की उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम एनआईडीडीसीपी के कार्यान्वयन से पूरे भारत में आयोडीन अल्पता विकार आईडीडी में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं:

कुल घेंघा दर (टीजीआर) में कमी: इस कार्यक्रम से देशभर में आयोडीन की कमी के प्रमुख संकेतक घेंघा की कुल दर में काफी हद तक कमी आई है।

आयोडीन युक्त नमक उत्पादन और खपत में वृद्धि: आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन सालाना 65 लाख मीट्रिक टन एमटी तक पहुंच गया है, जो भारतीय आबादी की आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विनियामक उपाय: खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 के अधिनियम 2.3.12 के अंतर्गत, प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए सामान्य नमक की बिक्री तब तक प्रतिबंधित है जब तक कि नमक आयोडीन युक्त न हो, राष्ट्रव्यापी आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

निगरानी प्रयोगशालाओं की स्थापना: आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, दिल्ली में स्थापित की गई है। साथ ही एनआईएन हैदराबाद, एआईआईएच एंड पीएच कोलकाता, एम्स और एनसीडीसी दिल्ली में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। ये प्रयोगशालाएँ आयोडीन के स्तर के लिए नमक और मूत्र परीक्षण का प्रशिक्षण, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण करती हैं।

राज्य – स्तरीय कार्यान्वयन: 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों में आईडीडी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं और इतनी ही संख्या में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य आईडीडी निगरानी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ: आईडीडी को रोकने के लिए नियमित रूप से आयोडीन युक्त नमक के सेवन के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाए गए हैं।

आयोडीन की कमी से निपटने के वैश्विक प्रयास

आयोडीन की कमी से निपटने के वैश्विक प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें आयोडीन अल्पता दिवस जैसी पहल प्रमुख है, जो थायरॉयड के कार्य, वृद्धि और विकास में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर, अनुमानित 1.88 अरब लोगों को अपर्याप्त आयोडीन सेवन का खतरा है, जिससे स्कूल जाने वाले लगभग 30: बच्चे प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने 1993 से सार्वभौमिक आयोडीनयुक्त नमक का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप 120 से अधिक देशों ने आयोडीनीकरण कार्यक्रम अपनाया है। इन ठोस प्रयासों से पूरे भारत में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

अंत में, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस एनआईडीडीसीपी जैसी राष्ट्रीय पहल और डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के नेतृत्व वाले वैश्विक प्रयासों के माध्यम से आयोडीन की कमी संबंधी विकारों को रोकने में हुई प्रगति की याद दिलाता है। निरंतरता और निगरानी लगातार सफलता सुनिश्चित करेगी, अंतत: स्वस्थ आबादी और दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार में योगदान देगी।

नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यकः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 9 करोड़ रुपये की लागत से बने ब्लॉक-सी भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद वह

महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने दो लाख रुपये देने की घोषणा की।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आरकेएमवी की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और साइंस ब्लॉक के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। वर्तमान राज्य सरकार ने सी-ब्लॉक के निर्माण के लिए छः करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई है। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो तथा इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा ''हमारा उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। यह चिंता का विषय है कि हम गुणात्मक शिक्षा में देशभर में 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं होगा और हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। लड़कियों की शादी योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 की गई है। लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने 'हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम-1972 में संशोधन किया है। नए कानून में पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को 150 बीघा भूमि की एक अलग इकाई रखने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

दिवाली से पहले घोषित होंगे छः पोस्ट कोड के नतीजे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दिवाली से पहले छः लंबित पोस्ट कोड के नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें पोस्ट कोड 939 (जेओए आईटी) के लिए 295 पद, पोस्ट कोड 903 (जेओए आईटी) के लिए 82 पद, कॉपी होल्डर के लिए पोस्ट कोड 982, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 992, साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट कोड 994 और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 997 शामिल हैं।

आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी क्षेत्र में युवाओं को पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले प्रदेश के युवाओं के लिए इन छः लंबित पोस्ट कोड का परिणाम राज्य सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमण्डल उप-समिति ने अब तक 21 लंबित पोस्ट कोड के परिणामों की घोषणा की अनुमति दी है, जिनमें से पोस्ट कोड 817,999 और 969 के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।

उन्होंने परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि छः परीक्षाओं के परिणाम दिवाली से पहले घोषित कर दिए जाएंगे और शेष 12 पोस्ट कोड के परिणाम नवम्बर माह में घोषित किए जाएंगे।

कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए मुआवजा राशि का आवंटन शुरूः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट की घोषणा को पूरा करते हुए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मुआवजा राशि देने का कार्य शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र के जुगेहड़ गांव के भूमि मालिकों को मुआवजा राशि के तौर पर कुल 32.50 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। वहीं, इन भूमि मालिकों को मुआवजे के साथ-साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिनकी भूमि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जुगेहड़ गांव के भूमि मालिकों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि यह उनकी वर्षों से लंबित मांग थी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है ताकि क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे सरकार का जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने का सपना साकार होगा।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अडडे के प्रस्तावित विस्तारीकरण से हवाई पट्टी की लंबाई 1,376 मीटर से 3,010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जिससे यहां एयरबस ए-320 हवाई जहाज की उड़ानों का संचालन संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे जिससे जिला कांगड़ा के लोग आर्थिक तौर पर समृद्ध होंगे और उनके जीवन में खुशहाली आएगी।.

'एम्बेसडर मीट' आयोजन से कुल्लू दशहरा को मिलेंगे नए आयामः सुन्दर सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के अवसर पर कुल्लू जिला में 'एम्बेसडर मीट' आयोजित करने की राज्य सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि छः देशों के राजदूत इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। इनमें इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, रूस, अमरीका और किर्गिस्तान के राजदूत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से कुल्लू दशहरा को नए आयाम मिलेंगे और विश्वभर में इसकी ख्याति और बढ़ेगी। इस आयोजन से हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों और परम्पराओं को वैश्विक स्तर पर लोगों को और अधिक जानने व समझने का अवसर प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि थाइलैंड और उज्बेकिस्तान के कारीगरों को भी प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा उत्सव के धार्मिक और सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे उत्सव के बहुआयामी पहलुओं से भी सभी को रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरे का इतिहास 17वीं शताब्दी से भी पूर्व का है। इसमें कुल्लू घाटी के मुख्य देवता भगवान श्री रघुनाथ जी का रथ विजय दशमी के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं द्वारा सुल्तानपुर के ऐतिहासिक मंदिर से बाहर निकाला जाता है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस भव्य आयोजन में 332 स्थानीय देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के राजदूत निश्चित रूप से इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन की सुनहरी यादें अपने साथ ले जाएंगे और 'पहाड़ी' व्यंजनों का आनंद लेने के अलावा हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों की मनमोहक झलक भी देखेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव ने इस भव्य कार्यक्रम और एम्बेसडर मीट के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री राजदूतों की बैठक को संबोधित करेंगे और राज्य की विकास यात्रा के अलावा पहाड़ी लोगों के जीवन में राज्य के मेलों और त्योहारों के महत्व को भी साझा करेंगे।

प्रदेश सरकार के प्रयास ला रहे रंग, विदेशों में खुले रोजगार के द्वार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मुहिम रंग ला रही है और युवाओं का विदेशों में रोजगार पाने का सपना अब साकार हो रहा है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि श्रम एवं रोजगाार विभाग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट हिमाचल को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी ईपीएस फैसिलिटीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए डिमांड प्राप्त हुई है। तकनीकी और गैर तकनीकी वर्ग में यह पद अबूधाबी के परमाणु ऊर्जा संयंत्र व प्रोविस स्कूल (रियल इस्टेट कंपनी) में भरे जाएंगे।

चयनित हुए तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को प्रतिमाह 22,800 रुपये से लेकर 1,14,450 रुपये वेतन प्रदान किया जाएगा।

आवेदकों को योग्यता के तौर पर दसवीं पास, आईटीआई इलैक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लंबर, लिफ्ट व मशीन ऑपरेटर, सहायक तकनीशियन, पेंटर, अंग्रेजी का आधारभूत ज्ञान, वैध पासपोर्ट और आयु सीमा 21-40 वर्ष होनी चाहिए।

अबूधाबी में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। अबुधाबी स्टैंपिंग वीजा के लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली में चिकित्सा परीक्षण और वीजा स्टैंपिंग के लिए आना होगा।

वहीं दुबई में सामान इत्यादि की डिलीवरी के लिए बाइक चालक (आयु सीमा 21-45) भी भर्ती किए जाएंगे। आवेदकों के लिए योग्यता के तौर पर दसवीं पास, आधारभूत अंग्रेजी का ज्ञान, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस और वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है।

चयनित बाइक चालकों को दो साल के अनुबंध पर रखा जाएगा। उन्हें आवास, बाइक, पेट्रोल और सिम कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। इन बाइक चालकों को दो माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिस दौरान इन्हें सात हजार रुपये भोजन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद इन्हें 34 हजार रुपये मासिक और 26 हजार रुपये अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

इच्छुक आवदेक बायोडाटा, पासपोर्ट और प्रमाण-पत्रों की प्रति के साथ एक सप्ताह के भीतर जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

डल और खजियार झील के पुनरुद्धार के लिए बुलाए गए झील संरक्षक और भू-वैज्ञानिक

शिमला/शैल। धर्मशाला के नड्डी स्थित डल झील में हो रहे रिसाव को रोकने और झील के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के लिए उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने जल शक्ति, पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से मौके की रिपोर्ट ली और उन्हें झील के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश भी दिए।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि लाखों लोगों की धार्मिक आस्था व पर्यटन का केंद्र और छोटा मणिमहेश के नाम से विख्यात डल झील के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है और इसका जल्द पुनरुद्धार कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी और उसके बाद तुरंत पुनरुद्धार का काम शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि डल झील में रिसाव को रोकने के लिए जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा भारत के लेकमैन के नाम से विख्यात आनंद मल्लिगावड के संपर्क में हैं। इसके अलावा भू-वैज्ञानिकों को भी विशेषज्ञ राय के लिए बुलाया गया है।

आनंद मल्लिगावड बेहद कम लागत से प्रकृति के अनुकूल प्रभावी तकनीकों का स्वयं विकास करके कई झीलों का कायाकल्प कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पर्यावरणविदों के साथ भी संपर्क किया गया है।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा 2004-05 से अब तक समुद्र तल से 1,775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डल झील के पुनरुद्धार पर करीब 31 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जबकि करोड़ों रुपये खर्च होने की भ्रामक खबरें प्रकाशित कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इसके साथ ही खजियार झील के कायाकल्प के लिए भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक और अध्यात्मिक महत्व के स्थलों के संरक्षण लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए कहा कि डल झील के वास्तविक सौंदर्य को जल्द निखारा जाएगा और लोगों की आस्था का यह केंद्र जल्द नए स्वरूप में दिखेगा।

बैठक में निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक भाटिया, डीएफओ धर्मशाला दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव जीएडी एवं वन प्रवीन कुमार टाक और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित शर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 31 अक्तूबर तक दुरूस्ती के लम्बित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग की एक समीक्षा बैठक में सभी लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित मामलों का निपटारा किया जा रहा है तथा इसमें और तेजी लाई जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलना चाहिए जिस पर राजस्व अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर-द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा करना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों और उपायुक्तों को दुरूस्ती के सभी लम्बित मामलों का 31 अक्तूबर, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त लम्बित राजस्व मामलों की समीक्षा के लिए अपने-अपने जिलों में एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती करें और इसकी सूचना सरकार को भेंजे ताकि लम्बित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाया जा सके।

उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए उपायुक्तों को नायब तहसीलदार तक खाली पड़े पदों को भरने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह नवम्बर माह में इस मामले की दोबारा समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले साल आई आपदा के प्रभावितों के लिए किए गए राहत कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज के रूप में 4500 करोड़ रुपये जारी किए हैं तथा इस धनराशि से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने साइबर विंग के सी.वाई-स्टेशन का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के 'सी. वाई-स्टेशन' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पूरे सप्ताह चौबिस घंटे कार्य करेगा और यह साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टॉल-फ्री नम्बर-1930 पर दर्ज करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सी. वाई-स्टेशन' लोग रियल टाइम में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं खास तौर पर आर्थिक अपराध से जुड़ी शिकायतें। उन्होंने कहा कि सिटिजन फाइनैन्शिल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एण्ड मेनेजमेंट सिस्टम के द्वारा यह आर्थिक धोखाधड़ी के ब्लॉकिंग या लीन मार्किंग ग्रहणाधिकार अंकन को सुगम बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह डाटा सेंटर राज्य के नोडल हब के रूप में स्थापित होकर राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जिला पोर्टल की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखेगा। यह भविष्य की योजनाओं के लिए मुख्य निर्णायक केंद्र के रूप में कार्य करते हुए शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में डाटाबेस भी बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सी. वाई-स्टेशन नवीन प्रौद्योगिकी से लैस होगा और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। इस स्टेशन में प्रशिक्षित ऑप्रेटर तैनात किए गए हैं और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग और प्रभावी फोलो-अप आदि सुविधाओं के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर की सुविधा भी है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की नेटवर्क अवसंरचना हिमाचल प्रदेश साइबर ढांचे और केंद्रीकृत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मध्य महत्त्वपूर्ण सामरिक संबंध स्थापित करेगा। यदि किसी बैंक या आर्थिक संस्थान को कोई शिकायत सुधार के लिए भेजी जाती है तो यह डाटा सेंटर शिकायतकर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि यह विभाग नवीन प्रौद्योगिकी का अपनी कार्य प्रणाली ज्यादा से ज्यादा समावेश करे। आधुनिकीकरण के ये प्रयास पुलिस विभाग में पारदर्शिता, प्रतिक्रिया और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं जिससे अन्ततः लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। आधुनिक प्रणाली को अपनाने से राज्य पुलिस नई चुनौतियों को प्रभावी तरीके से समाधान कर सकेगी। इससे सशक्त समाज सामाजिक संबंध स्थापित होंगे जो हिमाचल को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।

एसजेवीएनएल और पीडब्ल्यूडी के बीच सड़कों के विस्तारीकरण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग एवं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य सुन्नी-लूहरी सड़क, एमडीआर-22 (घरट नाला-खैरा) एवं शिमला से मंडी, एमडीआर-76 (ढली-देवीधार) की सड़कों के विस्तारीकरण परियोजना से संबंधित लगभग 70 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस समझौते से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पूर्व में उनके दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सहयोग से उन्होंने पांच सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। इनमें सलापड़-तत्तापानी-सुन्नी-खैरा-लूहरी सड़क मार्ग शामिल हैं। इससे न केवल करसोग बल्कि आनी, कुमारसेन, रामपुर तथा किन्नौर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी यह सड़क विकासात्मक परियोजना का एक हिस्सा है। चीन सीमा के नजदीक होने के कारण यह सामरिक महत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर एसजेवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सुशील कुमार शर्मा ने शिमला ग्रामीण के सुन्नी एवं लूहरी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। एसजेवीएनएल एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिमला ग्रामीण के पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के कामकाज की समीक्षा करते हुए महाविद्यालय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाये जा रहे नए परिसर में विश्व स्तरीय तकनीक से लैस आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं और मरीजों के लिए यहां 292 बिस्तर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय में थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन, हाई एंड एक्स-रे मशीनें, डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों सहित अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दो आईसीयू वार्डों में 10-10 बिस्तर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जोल सप्पड़ में 20 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय को बिजली की डबल सप्लाई से जोड़ा गया है, ताकि उपचार में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आये। उन्होंने परिसर में 15 दिन के भीतर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्राध्यापक तैनात हैं। चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी कोर्स में सीटें बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में उपचार के लिए ज्यादा मरीज आ रहे हैं, उनमें अधिक डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के वॉक इन इंटरव्यू और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि 150 स्टाफ नर्सें तैनात करने को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त नर्सें तैनात की जाएंगी। हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार डॉक्टर और नर्सें उपलब्ध होंगी, ताकि मरीजों को बेहतरीन इलाज मिल सके।

सुक्खू ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एमरजेंसी मेडिसन, रेडियोलॉजी और कॉर्डियोलोजी किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं तथा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में इन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही 200 बिस्तर क्षमता का मातृ एवं शिशु अस्पताल तथा छात्राओं के लिए दो हॉस्टल बनना भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की जांच के लिए अपनी आधुनिक लैब भी तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के दूसरे चरण में 300 बिस्तर क्षमता का मेडिकल ब्लॉक, स्टेट कैंसर अस्पताल, सुपर स्पेशयल्टी और नर्सिंग कॉलेज, छात्रों और मरीजों के लिए अन्य सुविधाओं का सृजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 2.30 करोड़ रुपये के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर में 2.30 करोड़ रुपये की लागत से तैयार विभिन्न सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बस स्टैंड हमीरपुर के सामने रानी झांसी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने भोटा चौक पर वर्षा शालिका, वार्ड नंबर दो में पार्क का सौंदर्यीकरण, गांधी चौक के नवीनीकरण कार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) के सामने निर्मित पार्क, स्ट्रीट वेंडर मार्केट भोटा, उपायुक्त कार्यालय के समीप निर्मित एस्पिरेशनल टॉयलेट तथा प्रताप नगर चौक, डांग कुआली चौक व पुरी चौक के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हमीरपुर में विभिन्न स्थलों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर शहर को सुंदर बनाने में उनकी व्यक्तिगत रुचि है। नया बस स्टैंड बनने के बाद पुराने बस स्टैंड पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

जब वित्तीय स्थिति ठीक है तो रेल विस्तार में अपना हिस्सा क्यों नहीं दे पा रही सरकार?

केंद्रीय सहायता पर प्रदेश भाजपा नेता हुए आक्रामक

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार केन्द्र के सहयोग के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने यह ब्यान दिया है तब से प्रदेश सरकार और प्रदेश भाजपा के नेताओं में केंद्रीय सहायता को लेकर वाकयुद्ध छिड़ गया है। क्योंकि नड्डा को जवाब देते हुये मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह कहा था कि यह एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मुख्यमंत्री के इस जवाब पर भाजपा नेता पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने हिमाचल में केन्द्र प्रायोजित चल रही 33 योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष के सात महीनों में 2197.26 करोड़ केन्द्र द्वारा दिये जाने का ब्योरा जारी किया है। विक्रम ठाकुर ने हर योजना में जारी हुई राशि के आंकड़े सामने रखे हैं। सुक्खू सरकार इन आंकड़ों को झुठला नहीं पायी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की भागीदारी के हिस्से का पैसा जारी नहीं कर रही है। जब राज्य सरकार योजना लागत का अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं करेगी तो निश्चित रूप से उस योजना का काम रुक जायेगा। प्रदेश में जो रेल लाइन विस्तार चल रहा है उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 की है। प्रदेश सरकार को लागत का 25 प्रतिशत खर्च देना है। लेकिन प्रदेश सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है। इसके लिये रेलवे बोर्ड ने प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम पत्र भेजा है। इस समय भानुपल्ली- बिलासपुर-बरमाणा रेल लाइन और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का काम चल रहा है इसमें 75:25 खर्च की हिस्सेदारी है। यदि प्रदेश सरकार यह पैसा नहीं दे पाती है तो निश्चित रूप से काम प्रभावित होगा। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये फॉरेस्ट कलियरैन्स का 30 करोड़ रूपया प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाया जाना है। लेकिन लम्बे अरसे से सरकार यह रकम जमा नहीं करवा पा रही है। इससे कांगड़ा का विकास प्रभावित हो रहा है। स्मरणीय है कि जब कठिन वित्तीय स्थिति का सदन में हवाला देकर वेतन भत्ते निलंबित करने का फैसला लिया था तब उसके दूसरे ही दिन यह कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नही है। वेतन भत्ते निलंबित करने का फैसला वित्तीय संचालन सुधारने के लिये लिया गया था। उसके बाद कर्मचारियों और पैन्शनरों को एडवांस में वेतन और पैन्शन का भुगतान करके यह संदेश दिया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक है कोई संकट नहीं है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि जब जब वित्तीय स्थिति ठीक है तो फिर रेल विस्तार के लिये प्रदेश में चल रही योजनाओं में सरकार अपने हिस्से की भागीदारी क्यों जमा नहीं करवा रही है? केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये फॉरेस्ट क्लीयरैन्स के 30 करोड़ अब तक जमा क्यों नहीं करवाये गये। क्या सरकार चाहती है कि प्रदेश का हिस्सा जमा न होने पर जब यह काम रुक जायेगा तब इसके लिये आराम से केन्द्र पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि प्रदेश का विकास रोक दिया गया। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से प्रदेश भाजपा के नेता मुखर होकर सरकार पर आक्रामक हो गये हैं उसके परिणाम अन्ततः गंभीर होंगे। लेकिन केन्द्रीय सहायता के योजनावार आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश सरकार और कांग्रेस के नेताओं को अपना पक्ष रखना कठिन हो जायेगा। इन आंकड़ों के अनुसार पिछले सात माह में सरकार को केंद्र से यह मिला है।

पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों में (1 अप्रैल से 12 अक्तूबर तक) प्रदेश को केंद्र प्रायोजित 33 योजनाओं के तहत 2197.26 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

ठाकुर ने बताया कि प्रमुख योजनाओं में मनरेगा (MNREGA) के तहत 395.93 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 196.32 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 162.75 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.04 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 582.47 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्रों में 4.47 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इसके साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपये, जबकि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 19.36 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि न्यायपालिका, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण और सिंचाई, शिक्षा, और बच्चों के कल्याण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी केंद्र ने भरपूर सहायता प्रदान की है।

हिमाचल प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा सुक्खू सरकार:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कॉस्ट कटिंग के नाम पर जेई, एसडीओ, एक्सईएन के पद खत्म कर रही है। इंजीनियर सरकार और विभाग पर बोझ नहीं होते। जो काम करते हैं उससे संबंधित विभाग बेहतर काम करता है। सरकार पर वास्तविक बोझ सीपीएस और कैबिनेट रैंक के साथ बनाए गए सलाहकार और ओएसडी हैं। जिन पर हर महीने लाखों रुपए का खर्च हो रहा है। लेकिन सरकार कॉस्ट कटिंग के नाम पर इंजीनियर को हटा रही है। उनके पद खत्म कर रही है। जबकि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से सरकार अपने मित्रों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। अगर सरकार को कॉस्ट कटिंग करनी है तो सबसे पहले असंवैधानिक रूप से बनाए गए सीपीएस को हटाए। सलाहकारों की फौज को हटाए। लेकिन सरकार आठ-दस हजार की रुपए की नौकरी पर करने वाले आउटसोर्स के कर्मियों को हटाती है। आउटसोर्स कर्मियों की तनख्वाह रोकती है। ठेके पर काम करने वाले सुरक्षाकर्मियों और सफाई कर्मियों का वेतन रोकती है। दूरदर्शिता और मानवीय संवेदना से भी को दूर है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। विकास के बजाये भ्रष्टाचार को प्राथमिकता देती है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय की बजाये संवादहीनता रखती है। आज हिमाचल में कल लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो केंद्र के सहयोग से चल रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश में पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं तो उसके पीछे का सहयोग और हिमाचल से जुड़े भाजपा के नेताओं के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का फीता काटते हुए कहते हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया। जबकि सुक्खू सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालने संस्थान बंद करने, इंजीनियर के पद समाप्त करने, लोगों पर टैक्स का बोझ डालने, महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आजकल मुख्यमंत्री जिन कार्यों का फीता काटते हैं उनमें कांग्रेस सरकार ने एक भी पैसे का योगदान नहीं किया है। सभी कार्यों का शिलान्यास, बजट प्रावधान से लेकर अन्य सभी प्रकार की क्लीयरेंस पूर्व सरकार द्वारा ही की गई थी। जिन्हें वह आज लोकार्पित कर रहे हैं। हां इन सभी परियोजनाओं में सुक्खू सरकार का बस इतना योगदान है कि उनके द्वारा लगाए गए अड़ंगों की वजह से परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हुई। मुख्यमंत्री जिन जगहों का फीता एक बार काटकर संतुष्ट नहीं हुए वहां दूसरी बार भी जाकर फीता काटा है। अब मुख्यमंत्री पूर्व की भाजपा सरकार को कोसने के बजाये प्रदेश के लोगों को यह बताएं कि उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए क्या कार्य किये हैं और यह भी बतायें की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश के लोगों से क्या-क्या छीना है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार जब अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाने में नाकाम हो गई तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने निशाने पर ले रही है। सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार होता रहे और भ्रष्टाचार की बातें अखबारों में न छपे, मीडिया के जरिए लोगों के सामने न आये। इसलिए सरकार में बैठे लोग अलग-अलग तरीके से मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। सरकार के खिलाफ विपक्षी नेताओं के आरोपों से जुड़ी कोई खबर छपने ना पाये, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर आ गयी है। चाहे जैसे करके वह पत्रकारों को डरा धमका कर सरकार के खिलाफ खबरें लिखने पर अंजाम भुगतने का माहौल बनाया जा रहा है। आज सुक्खू सरकार और उससे जुड़े लोग जो कर रहे हैं वह वह सीधे-सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है और संविधान के द्वारा प्रदत्त दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार ने पत्रकारों को हर तरह से प्रताड़ित करने के देश भर के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे यह लोग समझ लें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है पुलिस द्वारा डराओ-धमकाओं की नीति से नहीं।